

प्रेषक,

८२
 डी०पी० गैरोला,
 प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
 उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

श्री अभिषेक घौड़री,
 अधिवक्ता,
 53-लायर्स चैम्बर्स गार्डन्स,
 मा० उच्चतम न्यायालय,
 नई दिल्ली-110001

न्याय अनुभागः

देहरादून : दिनांक ॥ जुलाई, 2012

विषय : मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु एडवोकेट ऑन रिकार्ड के रूप में आवद्ध किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने आपके आवेदन पर सम्यक विद्यारोपरान्त मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकार्ड के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक आवद्ध किये जाने का निर्णय लिया है।

- 2- उक्त आवद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह किसी भी समय बिना किसी पूर्ण सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- 3- आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-69/XXXVI(1)/2010-43-एक(1)/03 दिनांक 25-03-2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।
- 4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ कि यदि सहमत हों तो कृपया अपनी लिखित सहमति उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय

(डी०पी० गैरोला)
 प्रमुख सचिव

संख्या: 192(1)/XXXVI(1)/2012-75/2007 टी०सी० तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा० मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महाधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
- 3- महासचिव, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 4- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के निजी सचिव।

क्रमशः 2

६
 श्रीमति विजय विजय